वर्ष-10//अंक-24// सितम्बर // 2023
ISSN 2454–5805
RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

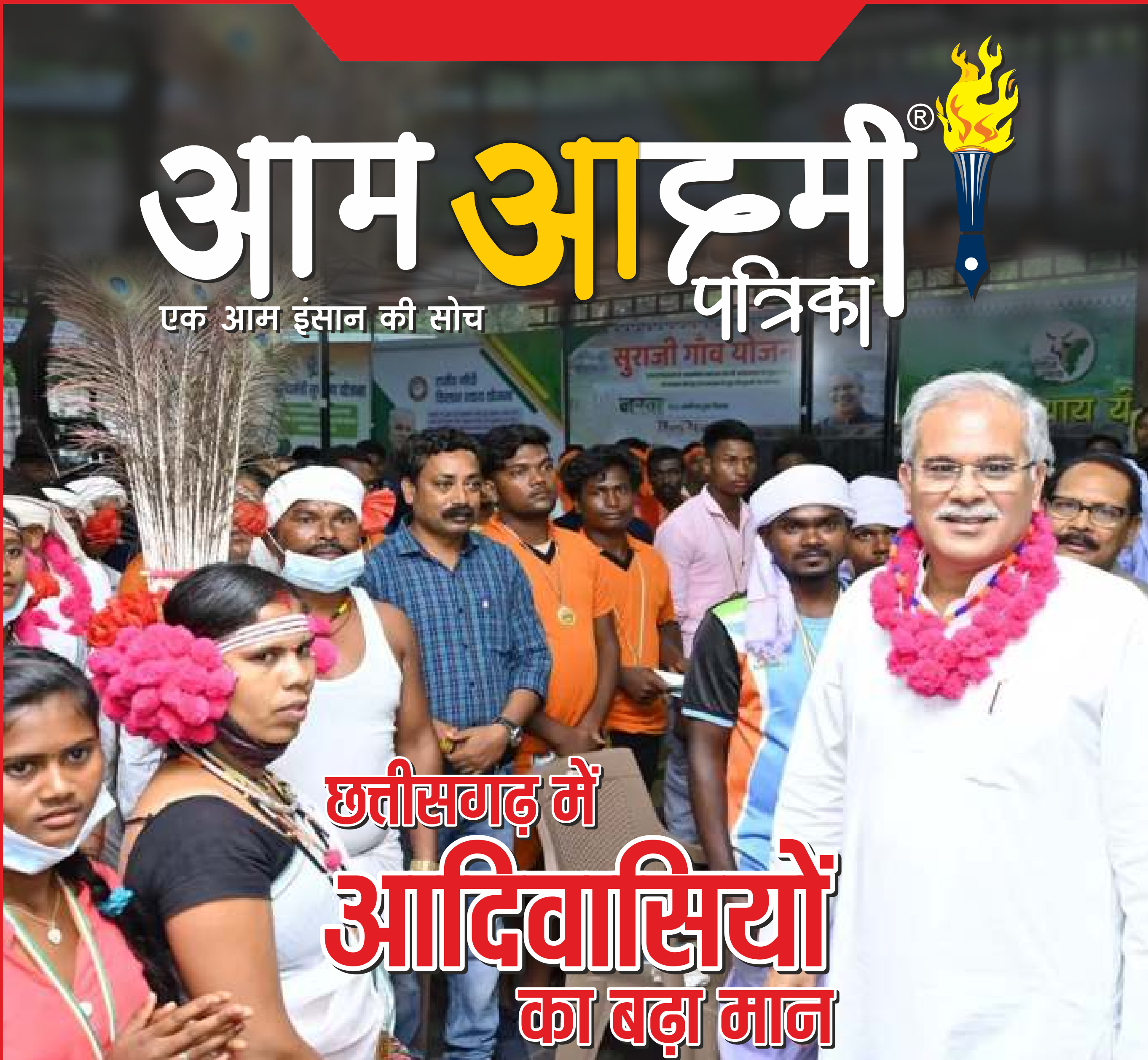

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बढ़ा मान

भूपेश सरकार में हो रहा संस्कृति का संरक्षण, आदिवासी परब और परंपराओं को मिल रहा बढ़ावा

बघेल सरकार बढ़ा रही कमाई की रफ्तार, रीपा में महिलाओं को मिल रहा रोजगार

05

चिटफंड कंपनी में निवेश कर जीवनभर की कमाई गवां चुके थे निवेशक

12

मोबाइल मेडिकल यूनिट में मिल रहा मुफ्त इलाज और दवाइयां

20

पशुधन ने बदली रूपाली की जिंदगी, गांव में ही दिखाई दे रहा सुनहरा भविष्य

www.aamaadmi.in

eyes events & advertising

CREATIVITY
IS TAKING A SIMPLE THING AND BRINGING IT TO LIFE

EVENTS | EXHIBITIONS | CORPORATE FILMS | VIDEO COMMERCIAL

Mo. : 97555-23831 www.eyesevents.in Follow us on

आम आदमी पत्रिका
वर्ष-10//अंक-24// सितम्बर // 2023

प्रबंध संपादक	:	उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज	:	प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	:	नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	:	प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर	:	देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	:	आइज इवेंट्स
मार्केटिंग मैनेजर	:	किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	:	काजल सिंह
अकाउंट असिस्टेंट	:	प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	:	योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय
965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in
कार्यालय
प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक
उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

सितम्बर 2023

इस अंक में

गरीबों को मिला आशियाना: खुद के पक्के मकान का सपना हुआ साकार,

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए स्वयं का आवास एक सपने से कम नहीं. ऐसे कई जरूरतमंद परिवारों के खुद के पक्के मकान का सपना अब प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हो रहा है.

10

सौर सुजला योजना किसानों को वरदान: 06

रायपुर. राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

मत्स्य बीज उत्पादन से मिला 'आमदनी का फल' 14

छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब से मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है, तब से मत्स्य कृषकों को बिजली दर में छूट.

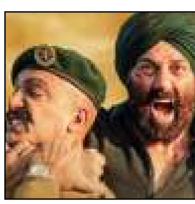

पठान के बाद गदर 2 ने की बंपर कमाई, 22

22 साल बाद पर्दे पर लौटी तारा और सकीना की लव स्टोरी ने गदर मचा दी है. फिल्म इस साल की दूसरी ऐसी फिल्म में अपना नाम शुमार कर की है.

प्रदेश में चहुं ओर फैल रही शिक्षा की ज्योति, आत्मानंद स्कूल से संवरी विद्यार्थियों की जिंदगी, 26

प्रदेश की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल से लाखों बेटे, बेटियों की जिंदगी संवर रही है.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से समृद्ध होती खेती-किसानी 28

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला है.

50 हजार लगाएं और लाखों में कमाएं 31

मुर्गीपालन व्यवसाय जैसे विकल्प उन विकल्पों में से एक हो सकते हैं जो न केवल आपको लाभ दिलाएंगे बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे.

जरूरी थी दामों में कटौती...

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

रसोई गैस का सिलेंडर एक साथ 200 रुपये सस्ता हो गया है, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। चर्चा तेज हो गई है कि सरकार आने वाले दिनों में लोगों को किन-किन मदों में राहत दे सकती है। चंद्रयान और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की जबर्दस्त सुर्खियों के बावजूद लाखों परिवारों के लिए सबसे बड़ी खबर यही थी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसके ऊपर 200 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी उनके लिए सिलेंडर 400 रुपये सस्ता हो गया है। इसके साथ ही 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम भी 158 रुपये घटाए गए हैं। इसकी कीमत पिछले महीने भी 99.75 रुपये कम हुई थी। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन देने का भी एलान किया है, जिसके बाद इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। गैस के दाम में कटौती से करीब 35 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी। इस कटौती के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी हर सिलेंडर पर 200 रुपये की रकम सरकार पेट्रोलियम कंपनियों के खाते में डालेगी।

गैस के दामों में कटौती की मांग काफी समय से हो रही थी और विपक्षी पार्टियां रसोई गैस के दाम को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगातार जुटी थीं। इसके लिए वे 2014 के चुनावों से पहले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्री स्मृति ईरानी के पुराने बयानों को भी याद दिलाती रहती हैं। अब जब दाम घटाने का एलान हो गया है, तब भी उन्हें राजनीति दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले गैस का 200 रुपये सस्ता होना रक्षाबंधन का तोहफा या चुनावी रेवड़ी?

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं, मगर विपक्षी नेताओं और विश्लेषकों को लग रहा है कि अब सरकार की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। अगर समय पर हुए, तो लोकसभा चुनाव मार्च के आसपास होने हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे, तो वह इसी साल विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव भी करवा सकती है। खैर, यह तो राजनीतिक मसला है, मगर बड़ा सवाल है कि अगर 200 रुपये की कटौती से करोड़ों परिवारों को राहत मिलती है, तो महंगाई पर कितनी राजनीति हो सकती है? क्या यह सोचना गलत है कि सरकार राहत देने का फैसला भी राजनीति के तराजू पर भली-भांति तौलने के बाद ही करती है? पिछले कुछ महीनों में महंगाई लगातार सुर्खियों में रही है। रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के ऊंचे दामों पर तो लगातार चर्चा होती रही है। खासकर इसलिए भी, क्योंकि पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरते रहे, फिर भी सरकार ने बाजार में पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भरना ही ठीक समझा। तब के पेट्रोलियम मंत्री कहा करते थे कि सरकार ऐसा इंतजाम कर रही है कि अगर वापस दाम बढ़ने लगे, तब भी उपभोक्ताओं को बचाकर रखा जा सके। मगर ऐसा हो न सका।

गैस सिलेंडर के मामले में इसीलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि यह मसला पहले भी राजनीति का मुद्दा बन चुका है। विपक्ष को लगता है कि अभी लोहा गरम है, जनता महंगाई से तपी हुई है, इसलिए यह मुद्दा कारगर हो सकता है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना में 500 रुपये में सिलेंडर देने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी यही करने का वादा किया है, तो अब शिवराज सरकार ने भी रक्षाबंधन पर सावन के महीने में 450 का सिलेंडर देने के साथ-साथ महिलाओं के खाते में 250 रुपये डालने का एलान कर दिया है।

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के तहत निवेशकों को उनकी राशि उन्हें वापस सौंपी है. कई निवेशक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवनभर की कमाई चिटफंड कंपनी में लगा दी थी, ताकि आज की बचत उनके भविष्य की कमाई बन सके. चिटफंड कंपनियों के झांसे मे आकर अपनी पूरी कमाई गंवा चुके लाखों निवेशकों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पैसे उन्हें वापस भी मिलेंगे. लेकिन सीएम भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से न सिर्फ पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिल रही है, बल्कि दोषियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है.

चिटफंड कंपनी में निवेश कर जीवनभर की कमाई गवां चुके थे निवेशक, सीएम ने दिलाया न्याय

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के निवेशक रामचंद्र निषाद बताते हैं कि उनके पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई 14 लाख रुपये चिटफंड कंपनी में निवेश कर दी थी. उनके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था. आज उनके खाते में 4 लाख 18 हजार रुपये वापस आए हैं. इसी तरह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रहन वाले रामनरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आज जो पैसे उनके खाते में आए हैं उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा.

धमतरी की रहने वाली शशि सोनी को उनके पैसे वापस मिले. इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आपकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिला है. मैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबी हुई थी. चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर मैंनें 15 लाख रुपये गंवा दिए थे. आज आपकी वजह से मुझे 8 लाख 55 हजार रुपये वापस मिल गए हैं. मैं इन पैसों से अपना कर्ज उतार दूंगी और अब अपनी बेटी को निश्चिंत होकर पढ़ा सकूंगी.

सौर सुजला योजना किसानों को वरदान: बलरामपुर के 9143 किसानों ने लिया लाभ

> रायपुर. राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस योजना से सोलर पंप प्रदाय कर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है. यह लाभ उन किसानों को दिया जाता है, जिनके पास जल स्त्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं और बोरवेल पहले से ही उपलब्ध है. राज्य में इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है.

इस संबंध में क्रेड़ा विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजनांतर्गत अब तक कुल 9143 पम्पों की स्थापना जिले के किसानों को प्रदान की जा चुकी है, जबकी वर्ष 2023 में 1500 पम्प की स्थापना की गई है, जिससे जिले के दुर्गम क्षेत्रों में भी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है. वर्षाजल पर आश्रित रहने वाले किसान अब योजना से लाभ लेकर दो से अधिक फसलों और साग-सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनके आय में निरंतर वृद्धि हो रही है. उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है.

विकासखण्ड रामचंद्रपुर के ग्राम चंदनपुर के किसान बनारसी मेहता बताते हैं कि उनके पास 1.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिस पर उन्होंने नलकूप खनन के उपरांत क्रेडा विभाग के सहयोग से सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना कराया था. वर्तमान में मेहता द्वारा धान एवं साग-सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सोलर पम्प की स्थापना के बाद दोहरी फसल का लाभ ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है.

विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम कृष्णानगर के किसान सुकुमार द्वारा वर्ष 2023-24 में 03 एचपी क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना कराया गया. उनके पास लगभग 1.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है. वे बताते हैं कि इस वर्ष वर्षा में विलम्ब होने के कारण धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन सोलर पम्प लगने से सही समय में धान की रोपाई का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब वे धान के अलावा साग-सब्जी का भी उत्पादन करेंगे.

किसान ले रहे दोहरी फसल का लाभ

जिले के ऐसे किसान जो वर्षा जल आधारित कृषि करते थे, उन्हें वर्षा की लेट-लतीफी होने से भारी नुकसान उठाना पड़ता था तो वहीं पानी की दिक्कतों से किसान रबी फसल नहीं ले पाते थे. लिहाजा दोनों फसलों में आर्थिक नुकसान की आशंका किसानों को बनी रहती है. इसी समस्या को देखते हुए शासन द्वारा सौर सुजला योजना प्रारंभ किया गया. सौर सुजला योजना से आज जिले के किसान रबी एवं खरीफ फसलों के साथ-साथ साग-सब्जियों का उत्पादन बिना परेशानी के कर रहे हैं. सौर सुजला योजना से पानी की समस्या खत्म होने से सभी प्रकार के कृषि सब्जी उत्पादन के साथ अन्य कार्य सुचारू तरीके से किया जा रहा है. किसान धान के साथ सब्जी फसल भी ले रहे है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है.

विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम कोटरकी के किसान आशामुनी ने बताया कि पहले खरीफ की फसल आसानी से हो जाती थी, लेकिन पानी की समस्या के कारण रबी की फसल लेने में दिक्कत होती थी. ऐन वक्त में बिजली की समस्या भी आ जाती थी, लेकिन अब सौलर पम्प लगने से बिजली और बिल दोनों की समस्या खत्म हो गई. अब वे खरीफ और रबी दोनों फसल को बड़ी आसानी से ले पा रहे हैं. इससे उनकी आमदनी बढ़ी है.

सोलर पम्प लगवाने के लिए कैसे करें आवेदन

वर्तमान में सौर सुजला योजनान्तर्गत जिले को 1500 पम्प लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस हेतु इच्छुक कृषक अपना आधार कार्ड, भूमि का खसरा, रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (पम्प अनुसार) 03 एचपी के लिए 03 हजार एवं 05 एचपी के लिए 4800 रुपये एवं स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स, पासबुक की छायाप्रति के साथ अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्रेडा या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं.

छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर, मैं भी आपकी तरह दुखी और चिंतित हूं...

प्रिय पाठकों आजकल की जटिल पढ़ाई, खुद को सबके सामने सबसे अच्छा साबित करने की दौड़ में सब कुछ मिलकर डिप्रेशन और स्ट्रेस बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बच्चों में सुसाइड के मामले बढ़े हैं। ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक 15 से 35 साल के बच्चों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। देश में रिकॉर्ड की गई आत्महत्याओं में से 35% इसी आयु वर्ग में होती हैं।

वैसे, तो हर उम्र के व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जा रही है, परंतु 15 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में इसकी संख्या अधिक सामने आती है। आत्महत्या करने के कई कारण हैं, परंतु भारत में इसके मुख्य कारणों में नौकरी का नहीं मिलना या नौकरी का छूट जाना, सामाजिक तौर पर मानसिक तनाव, बच्चों में पढ़ाई का तनाव, किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण का समय पर नहीं चुका पाना, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के चलते स्त्रियों पर मानसिक तनाव अथवा छेड़छाड़ या दुष्कर्म के बाद समाज के तानों से घबराकर भी आत्महत्या कर लेना एक मुख्य कारण है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों व विभिन्न शोध के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले या तो टीनएज में होते हैं या युवावस्था में। टीनएज प्रोबेशन का समय होता है। बच्चों में कई तरह के मानसिक व शारीरिक बदलाव होते हैं। कई नए हार्मोन बनते हैं। वे इस दौरान काफी संवेदनशील होते हैं। छोटी सी बात भी उनके मन पर गहरा प्रभाव डालती है।अक्सर माता-पिता बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक अपेक्षा करते हैं। दूसरों से उनकी तुलना करते हैं। अपेक्षित परिणाम न मिलने पर डाटते हैं। जबकि बच्चों को उनके मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत माता-पिता की होती है। अगर बच्चा चुप-चुप, अकेला और अलग-अलग रहने लगे तो उसे यूं ही न छोडें। इस संकेत को समझें और उनसे विनम्रता के साथ बात करें।

भारत का युवा इतना कमजोर हो गया है की वह परेशानियों से लड़ने की जगह आत्महत्या करना आसान समझ रहा है। वह आत्महत्या करते समय ये भी नहीं सोचता उसके बाद उसके परिजनों का क्या होगा। नयी रिपोर्ट से पता चला है युवाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे है पिछले कुछ सालो में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमे छोटे बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश की या उन्होंने आत्महत्या कर ली है ऐसे ही कुछ मामलो के बारे में बताते है। एक किशोर ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता ने उसके बाल जबरन कटवा दिए थे। एक और मामला सामने आया जिसमे एक किशोरी ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या का कदम उठाया क्योंकि उसकी माँ ने उसे खाना समय पे बनाने के लिए डाट दिया था। एक और किशोर ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके परिजनों ने उसे मोबाइल में गेम खेलने के लिए डांट दिया था।

आज के दौर में तनाव और भावना को हेल्दी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, यह अपने बच्चे को जरूर सिखाएं। इस तरह की मानसिक स्थितियों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को फिजिकल एक्टिविटी में बिजी कर लेना, या फिर हॉबीज में मन लगाना, खुद को शांत करने की टेक्नीक से मदद लेना या फिर दोस्तों और परिवार से अपने दिल की बात शेयर करना, ताकि वे आपको मुश्किल समय में सपोर्ट कर सकें।

भूपेश सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को मिला सुनहरे भविष्य का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ रहे हितग्राही

प्रदेश में पौने पांच सालों में भूपेश सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है. सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम सरकार ने किया है. लोगों ने जो भरोसा शासन पर जताया था उस पर सरकार खरा उतर रही है. योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का कहना है कि ये उनके सुनहरे भविष्य का एक मजबूत भरोसा है. जिसके लिए सभी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी जताया. जांजगीर-चाम्पा जिले में आज आयोजित भरोसे के सम्मेलन में बेरोजगार, जरूरतमंद हितग्राहियों को रोजगार, आत्मनिर्भर होने और अपने पैरों में खड़े होने का अवसर भी मिला. यहां हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियां भी वितरित की गई.

सम्मेलन में ग्राम नंदेली की जय मां चंडी दाई स्व सहायता समूह को 10 साल के लिए तालाब में मछली पालन के लिए पट्टा मिला. समूह की अध्यक्ष पितर बाई ने कहा कि गांव के तालाबों का पट्टा देकर मत्स्य पालन के लिए न सिर्फ जाल, आइसबॉक्स, बीज दिया जा रहा है, मछली पालन के व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी गरीबों और गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. आइसबॉक्स से लाभान्वित होने वाले ग्राम कमरीद के सूर्या युवा स्व सहायता समूह के अध्यक्ष ने बताया कि तालाब का पट्टा मिलने से मछली पालन के साथ रोजगार के नए अवसर मिला.

शासन की सहायता से अपने व्यवसाय को गति देंगी ये महिलाएं

ग्राम भड़ेसर की संगीता बाई, रेशमा बाई ने बताया कि उन्हें अंत्यावसायी विभाग से सिलाई मशीन मिला. वे सिलाई का काम करती है. शासन द्वारा 10 हजार रुपए का अनुदान मिला है. इतनी बड़ी राशि की छूट से उन्हें बड़ी राहत मिली है. अब नई मशीन से वह अपने सिलाई के व्यवसाय को और भी आगे बढ़ा पाएगी. कार्यक्रम में 219 हितग्राहियों को मशीन में अनुदान 21 लाख 90 हजार रुपये दिया गया. इसी तरह रेशम विभाग द्वारा 1940 हितग्राहियों को सिल्क समग्र योजना अंतर्गत कोसा धागाकरण के लिए 1 करोड़ 94 लाख रुपए की मशीनें दी गई.

कलाबाई पटेल का काम हुआ आसान

ग्राम पेंड्री की मां कुमारी और गोविंदा की कलाबाई पटेल बताया कि कोसा धागाकरण मशीन मिलने से अब उनका काम आसान हो गया है. उन्होंने बताया कि वे पहले थाई से धागाकरण करती थीं, अब मशीन से क्वालिटी के साथ कम समय में भी आसानी से धागाकरण कर लेंगी. कार्यक्रम में श्रम, महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि सहित अन्य विभागों की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया.

गरीबों को मिला आशियाना:
खुद के पक्के मकान का सपना हुआ साकार, कई परिवारों में आई खुशियां, 8 लाख 62 हजार से अधिक बने आवास

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए स्वयं का आवास एक सपने से कम नहीं. ऐसे कई जरूरतमंद परिवारों के खुद के पक्के मकान का सपना अब प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हो रहा है. उन्हें कच्चे मकानों के ढह जाने की चिंता और बरसात के सीलन भरी दीवारों से अब छुटकारा मिल चुका है. प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से हजारों परिवार अपने खुशियों के पल बिना किसी चिंता के साथ जी रहे हैं. छत्तीसगढ़ में आवासहीन परिवारों के लिए 8 लाख 62 हजार 839 आवास बनाए गए हैं. इसके अलावा 3 लाख 13 हजार 307 मकान बनाए जा रहे हैं, जो जल्द परिवारों को उपलब्ध होंगे.

बरसात के सीलन भरी दीवारों से मिला छुटकारा

पक्के मकान का सपने लिए परिवारों में से एक कोरिया जिले के ग्राम पंचायत कदरेवा में रहने वाले हीरालाल का परिवार भी था. हीरालाल काफी वर्षों से अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रहते थे, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था, जिससे उनके परिवार को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती थी. आर्थिक रूप से सशक्त न होने की वजह से उनके लिए पक्का मकान बनवाना संभव नहीं था.

बारिश के दिनों में सीलन आने की वजह से उनके परिवार को कई बीमारियां होती थी. इस बीच उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला. उन्होंने आवेदन किया और अब उनका पक्का घर बन के तैयार हो चुका है. वे अब चिंता मुक्त और खुश हैं. हीरालाल बताते हैं कि वे अपने आस-पास के लोगों और रिश्तेदारों को भी इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करते हैं.

सपने हुए पूरेः टूटा फूटा मकान अब बना पक्का

जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लोधमा निवासी 77 वर्ष के सिमोन मिंज का पक्का आवास बनाने का सपना अब पूरा हो गया है. सिमोन के पास दो कमरे की पुश्तैनी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें वे अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे. उनके आवेदन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में पक्का आवास बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई. शासन से मिली एक लाख 30 हजार रूपए की अनुदान राशि और स्वयं के बचत और बच्चों की कमाई से अतिरिक्त एक लाख रूपए की राशि मिलाकर उन्होंने स्वयं पक्का मकान बना लिया. सिमोन मिंज ने बताया कि आवास योजना का लाभ नहीं मिलता तो वह कच्चे एवं टूटे-फूटे मकान में निवास करते रहते. अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पक्के मकान में सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं. पक्का मकान का सपना पूरा होने से खुश सिमोन ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है.

स्लम क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बनी स्वास्थ्य योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट में मिल रहा मुफ्त इलाज और दवाइयां

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की दस्तक के साथ ही अब घरों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचने लगी है. प्रदेश के शहरी स्लम इलाकों में रह रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भूपेश सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है. जिसके तहत शहरी स्लम निवासियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है. सरकार की ये योजना स्लम में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हुई है. मोबाइल मेडिकल यूनिट पर लोग डॉक्टरों से अपना इलाज करा करा रहे हैं. साथ ही यहां से दवाइयां और 41 तरह के टेस्ट भी मुफ्त किए जा रहे हैं.

धमतरी नगर निगम के हटकेशर वार्ड मुख्यमंत्री स्लम के तहत लगाए गए शिविर में अपना इलाज कराने आए नंदकुमार ठाकुर बताया कि वे निजी स्कूल में वाहन चालक का काम करते है. कुछ दिनों से उनकी आंखों में जलन और खुजली हो रही थी. जिसका इलाज करवाने वे वार्ड में आई मोबाइल मेडिकल यूनिट आए. जहां उनकी निःशुल्क जांच कर आंख में डलाने की दवाईयां और गोलियां की गई. दो दिन तक लगातार सेवन करने और आंख में दवाई डालने के बाद नंदराम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई. वहीं इसी वार्ड में रहने वाले लखन लाल साहू ने बताया कि दो हफ्ते से उनके हाथ-पैर, पीठ और गर्दन में झुनझुनी और कमजोरी की तकलीफ थी. जिसका इलाज उन्होंने मोबाइल यूनिट शिविर में कराया, उन्हें दवाई के साथ ताकत की टॉनिक भी दिया गया था, जिससे उन्हें बीमारी से राहत मिली हैं. हाथ-पैर में झुनझुनी और कमजोरी में फर्क पड़ा है.

मोबाइल मेडिकल यूनिट में मिल रहा बीमारियों का इलाज

जिले के गरीब बस्तियों के लोग इलाज करा रहे हैं. मोबाइल यूनिट विभिन्न वार्डों में निर्धारित समय पर पहुंचती है. सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी बीमारियों का निःशुल्क इलाज कराने पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल का खर्च वहन कर पाना मुश्किल था. जबकि शिविर में उनका इलाज मुफ्त में हो गया और उन्हें अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़े और इलाज और स्वास्थ्य की जांच में कुछ खर्च नहीं करना पड़ा. नंदकुमार ठाकुर और लखन लाल साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घर तक अस्पताल पहुंचाने के लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हैं. जिले में अब तक 2 हजार 256 कैंप लगा कर 2 लाख 25 हजार 495 मरीजों का इलाज किया है.

56 हजार से ज्यादा मरीजों का मुफ्त लैब टेस्ट

इन मरीजों में से 56 हजार 892 मरीजों का मुफ्त लैब टेस्ट किया गया है. वहीं 1 लाख 78 हजार मरीजों को दवाओं का वितरण निःशुल्क किया गया है. वर्तमान में आंख की बीमारी के भी मरीज प्रतिदिन देखने को मिल रहे है. एमएमयू में आई फ्लू की बीमारी से पीड़ित लोगों का भी ईलाज कर निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है. जिले में अब तक एमएमयू के माध्यम से लगभग 510 लोगों का इलाज किया जा चुका है. एमएमयू में 41 प्रकार के विभिन्न लैब टेस्ट किये जाते हैं. इनमें खून, मल-मूत्र, थूक, टीबी, थायराइड, मलेरिया, टायफाईड की जांच कुशल लैब टेक्निशियन द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है.

कैंप लगाकर सुविधा मुहैय्या करा रहे डॉक्टर्स

अब जिले में स्लम बस्तियों के मरीजों को मुफ्त जांच, उपचार और दवा की सुविधा और बेहतर तरीके से मिल रही है. आधुनिक उपकरण से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाएं दे रही. इस मोबाइल मेडिकल यूनिटों में एमबीबीएस डॉक्टर जिले की स्लम बस्तियों में कैंप लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे है. एमबीबीएस डॉक्टरके साथ कैंप में मुफ्त दवा वितरण के लिए फार्मासिस्ट, मुफ्त लैब टेस्ट करने के लिए लैब मरीजों तक मुफ्त जांच, उपचार और दवा की सुविधा पहुंचाई जा रही है.

मत्स्य बीज उत्पादन से मिला 'आमदनी का फल'

छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब से मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है, तब से मत्स्य कृषकों को बिजली दर में छूट और निःशुल्क पानी और बिना ब्याज ऋण मिलने से उत्पादन लागत में बहुत कमी आई है. मत्स्य कृषकों की आमदनी लगातार बढ़ रही है. नतीजन छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यो में शामिल हो गया है. अब यहं मछली अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की इकाईयां भी आगे आ रही हैं और छत्तीसगढ़ राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार भी मिल चुका है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन लगातार विकास और प्रगति की ओर बढ़ रहा है. राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के तहत मत्स्य बीज उत्पादन कार्य से लेकर मत्स्य उत्पादन, मत्स्य विपणन का कार्य किया जा रहा है. राज्य मत्स्य बीज आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और भारत के अंतर्देशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में 6वें स्थान से 5वां बड़ा राज्य बन गया है.

पिछले पौने पांच वर्षों में राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन 251 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़ स्टेंडर्ड फ्राई हो गया है. मत्स्य बीज उत्पादन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मौसमी तालाबो में मत्स्य बीज संवर्धन कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालकों द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन किया जा रहा है. इस योजना से 5 हजार से ज्यादा मत्स्यपालक लाभ उठा चुके हैं. इसी तरह वर्ष 23-24 में भी 500 मत्स्य पालको द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन किया जा रहा है. पिछले पौने पांच सालों में 23 नए सर्कुलर मत्स्य बीज हेचरी की स्थापना की गई है. वर्तमान में कुल 92 मत्स्य सरर्कुलर हेचरी मत्स्य बीज उत्पादन के लिए उपलब्ध है. राज्य और देश के अन्य राज्यो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगाना,केरला और गोवा के मत्स्यपालकों के मांग के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज आपूर्ति की जा रही है.

क्या आप भी करना चाहते हैं खुद का व्यवसाय, सरकार दे रही है 5 लाख, जानिए कैसे करें अप्लाई ?

अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना में आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं. इस ऋण की ब्याज दर बैंकों की तुलना में कम है. पीएम मुद्रा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है. इस वजह से आसान किस्तों पर लोन दिया जाता है. इसमें आप 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. आइये जानते हैं इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

योग्यता

इस योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोन ले सकता है.

लोन देने से पहले यह जांचा जाता है कि आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर तो नहीं है. इसके साथ ही उनका क्रेडिट स्कोर कैसा है.

इस योजना में लोन लेने के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है.

आप इस लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितना लोन उपलब्ध है

इस योजना में लोन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. पहली श्रेणी शिशु है, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है. दूसरी कैटेगरी है किशोर, जिसमें 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. तीसरी और आखिरी कैटेगरी है तरुण, जिसमें 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. लोन पर ब्याज बैंक की दरों के अनुसार लिया जाता है.

आवेदन कैसे करे

मुद्रा लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे. आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस प्रूफ जैसे कई दस्तावेज होने चाहिए. लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

अब आपको मुद्रा लोन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
यहां आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और ओटीपी जनरेट करना होगा.
जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लोन आवेदन केंद्र का चयन करना होगा.
इसके बाद जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा.

अब सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा. इसके जरिए आप लोन की स्थिति जान सकते हैं

रेशम की डोर से महिलाओं की आमदनी मजबूत: बघेल सरकार बढ़ा रही कमाई की रफ्तार, रीपा में महिलाओं को मिल रहा रोजगार

छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाएं लाखों बरसा रही हैं. रीपा योजना के तहत धन की वर्षा हो रही है, जिसको मेहनतकश अपनी मेहनत से बटोर रहे हैं. महिलाओं की लाखों की आमदनी हो रही है. आत्मनिर्भर बन रही हैं.

सरकार की योजनाएं पैसे के साथ खुशियों की बारिश कर रही हैं, जिससे लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ रही है. घर के आंगन खुशियों का उजियारा फैल रहा है. टसर सिल्क, ये नाम तो आपने सुना ही होगा. टसर रेशम को जंगली रेशम भी कहा जाता है. टसर रेशम से बने कपड़े पहनने के शौकीनों की कमी नहीं हैं, सिल्क साड़ियां का बाजार आज भी गुलजार है. खास मौकों पर सिल्क कपड़ों का अपना अलग महत्व है. युवा से लेकर बुजुर्ग महिलाओं की पसंद में सिल्क साड़ियां पहले नंबर पर है. टसर सिल्क की समृद्ध बनावट और चटक गहरा रंग है, जो इसकी लोकप्रियता का कारण है.वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विभिन्न रीपा केंद्रों में रेशम धगाकरण का कार्य स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. महिलाएं इससे अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं.

राजनांदगांव जिले के ग्राम बघेरा की नारी शक्ति टसर सिल्क मटका स्पिनर स्व-सहायता की 15 महिलाओं ने जनवरी 2023 से रेशम धागाकरण का कार्य प्रारंभ किया. ये महिलाएं पहले खेती किसानी, मजदूरी और घर का काम करती थी. परिवार के साथ रहकर सीमित साधनों के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रही थी. समूह की महिलाओं द्वारा 4 लाख 50 हजार रुपए का रेशम धागा का उत्पादन किया गया, जिसमें इन महिलाओं को 1 लाख 40 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हुआ.

इसी तरह रीपा योजनान्तर्गत बस्तर जिले के ग्राम तुमेनार के रेशम धागा समिति की 20 महिलाओं रेशम धागाकरण का कार्य कर रही है. समूह की महिलाओं द्वारा कुल 6 लाख रुपए का धागा उत्पादन किया गया, जिसमें इन महिलाओं को 1 लाख 80 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हुआ. रीपा केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रेशम धागे का उत्पादन और विपणन करने में सक्षम बनाना है. इसके अलावा, उद्यम गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करना है और ग्रामीण आबादी विशेष रूप से महिलाओं को स्व-रोजगार के ढेर सारे अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना है.

सोलर सिंचाई पंपों से खेतों में हरियाली: सौर सुजला योजना से बदली किसानों की किस्मत, 1.37 लाख किसानों के खेतों में लगे सोलर पंप, सालभर हो रही खेती

छत्तीसगढ़ में दुर्गम क्षेत्रों तक भी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है. ऐसे क्षेत्रों जहां बारिश कम हो या जहां दूसरी फसल लेना हो वहां बारिश के मौसम के बाद भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था सौर सुजला योजना ने कर दी है. ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विभाग द्वारा प्राप्त सोलर पम्पों से खेतों से सिंचाई अब आसान हुई है.

गौरतलब है कि ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों को बढ़ावा देने हेतु क्रेडा द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों में शासन की महत्वाकांक्षी योजना सौर सुजला योजना अंतर्गत एक लाख 37 हजार से अधिक सोलर पंपों की स्थापना कर प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित सोलर पंपों की तुलना में सर्वाधिक है.

छत्तीसगढ़ ने सोलर सिंचाई पम्प स्थापना में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉरमेंस स्टेट नोडल एजेंसी का अवार्ड भी प्राप्त किया है.

प्रदेश के सैकड़ों किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर खेतों की प्यास बुझा रहे हैं, जिससे उपज में बढ़ोत्तरी के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ी है.

छत्तीसगढ़ में दुर्गम क्षेत्रों तक भी किसानों के खेतों में फसल लहलहा रही है. ऐसे क्षेत्रों जहां बारिश कम हो या जहां दूसरी फसल लेना हो वहां बारिश के मौसम के बाद भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था सौर सुजला योजना ने कर दी है. ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली की पहुंच अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विभाग द्वारा प्राप्त सोलर पम्पों से खेतों से सिंचाई अब आसान हुई है.

गौरतलब है कि ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों को बढ़ावा देने हेतु क्रेडा द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों में शासन की महत्वाकांक्षी योजना सौर सुजला योजना अंतर्गत एक लाख 37 हजार से अधिक सोलर पंपों की स्थापना कर प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित सोलर पंपों की तुलना में सर्वाधिक है.

छत्तीसगढ़ ने सोलर सिंचाई पम्प स्थापना में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉरमेंस स्टेट नोडल एजेंसी का अवार्ड भी प्राप्त किया है. प्रदेश के सैकड़ों किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर खेतों की प्यास बुझा रहे हैं, जिससे उपज में बढ़ोत्तरी के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ी है.

राज्य सरकार के कृषि विभाग व क्रेडा की ओर से रियायती दरों पर किसानों को सोलर सिंचाई पंप प्रदान किए जाते हैं. ऐसे अनेकों गांव तथा खेत खलिहान में सोलर पंप लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है, जहां बिजली पहुंच पाना संभव नहीं हैं. सुदूर वनांचल क्षेत्रों के किसानों के लिए सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है.

कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम कुड़ेली के किसान सुखराम प्रजापति बताते हैं कि उनके पास लगभग 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है. पहले वे सीजन में गेहूं की फसल लगाते थे, लेकिन वर्षाजल के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती थी. उनके खेत में 3 एचपी का सोलर पम्प लगा है, तब से पूरे वर्ष खेतों में हरियाली रहती है.

उन्होंने बताया कि पंप लगने के बाद उनकी आमदनी 60 हजार रूपए से अधिक हो गई है, इससे वे बहुत खुश हैं. वे 5 एकड़ में धान तथा सब्जी की खेती कर रहे हैं. इसी तरह ग्राम केसगवा के मोहर लाल बताते हैं कि सोलर पम्प लगने से पहले वे खेतों में केवल धान ही लगा पाते थे, लेकिन सोलर पंप लगने के बाद अच्छी खेती से आमदनी भी अच्छी हो रही है. कांकेर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र भानुप्रतापपुर के ग्राम कुंआपानी निवासी मालती बाई धनेलिया बताती हैं कि सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण पहले वह मानसून पर निर्भर रहती थीं. समय पर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाती थी, जब से उन्होंने अपने खेत में 03 हार्स पावर का सोलर पंप स्थापित किया है. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से दलहन, तिलहन की खेती से अच्छी आमदनी होने लगी है. उनके निजी तालाब में भी मछली पालन से लगभग 50-60 हजार रूपये प्रतिवर्ष कमाई हो जाती है. सौर सुजला योजना ने उनकी तकदीर बदल दी है. इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया है.

पशुधन ने बदली रूपाली की जिंदगी, गांव में ही दिखाई दे रहा सुनहरा भविष्य, गोबर बेचकर पूरे कर रहीं अपने सपने

> बीते साढ़े चार सालों में छत्तीसगढ़ के किसान, पशुपालक और ग्रामीणों के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है. इन योजनाओं ने पशुपालकों और किसानों के साथ न्याय किया है. शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा घुरवा बारी, ग्रामीणों के लिए आर्थिक विकास का सेतु साबित हो रही है.

ग्राम मदनपुर की रहने वाली रूपाली हलदार अब तक गोबर बेचकर 29 हजार 652 रुपये की कमाई कर चुकी है. उन्होंने बताया कि हम मजदूरी करते हैं इसलिए हमेशा उनके मन में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का विचार रहता था. ऐसे में शासन की गोधन न्याय योजना ने उन्हें एक अवसर दिया. आज योजना के तहत वो गौठान में हर दिन 70 से 80 किलो गोबर बेच रही हैं. इससे उनकी आर्थिक स्तर में काफी सुधार हुआ है.

पशुधन से आया बदलाव

रूपाली ने बताया कि पशुधन से ही उनके जीवन में ये बदलाव आया है. इसलिए उन्होंने गोधन से प्राप्त राशि, पशु शेड निर्माण में खर्च की. जिससे शासन की इस महती योजना से उनकी आवक बनी रहे और उनका परिवार तरक्की करता रहे. आज उनकी गायें छांव में रहती हैं, स्वस्थ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वो भविष्य में पशुधन की संख्या में वृद्धि करना चाहती हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहती हैं. अब उन्हें गांव में ही सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है.

मिश्रित फसलों की ओर बढ़ा छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान, अच्छी पैदावार के साथ-साथ 'धन' उगल रही धरती

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप क्रियान्वित योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है. राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लेकर राज्य के कृषक अब धान के अलावा अन्य फसलों की तरफ भी रुचि दिखा रहे है. किसान ग्रीष्मकालीन धान के साथ ही साथ अन्य फसलों जैसे कि गेहूं, अलसी, मसूर, मूंग की अच्छी पैदावार ले रहे हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 फीसदी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. राज्य का ज्यादातर क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है. कृषि में पर्याप्त निवेश और काश्त लागत में किसानों को राहत देने के लिए राज्य शासन किसानों के हित में योजनाएं संचालित कर रही है. जिसका लाभ लेकर किसान न सिर्फ बेहतर उत्पादन ले रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं.

इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा संचालित टरफा योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें उन्हें धान की जगह अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जार हा है. धान के अलावा दूसरी फसलों की कम पानी और कम लागत में अच्छी पैदावार होने से जिले के किसान अच्छी आय हो रही है.

योजना का लाभ लेते हुए बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के सिलतरा निवासी किसान राजेश यादव ने बताया कि उनके पास 1.5 एकड़ कृषि भूमि है. वे अपने खेत में धान की फसल बोते थे. इससे गर्मी में धान की फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती थी. फलस्वरूप धान की पैदावार पर भी असर पड़ता था. राजेश के अनुसार राज्य शासन की योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें धान के बदले अन्य फसलों जैसे गेहूं, मूंग, मसूर, मक्का की खेती कम लागत और कम पानी में किए जा सकने की जानकारी मिली.

कृषि विभाग द्वारा गेहूं बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर और प्रदर्शन के लिए मसूर बीज प्राप्त हुआ. राजेश ने गेहूं और मसूर की मिश्रित बुआई की. जिससे कम पानी में फसलों की अच्छी पैदावार हुई. जिससे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ. योजना से होने वाली अच्छी पैदावार और अच्छी आय को देखते हुए अब राज्य भर के किसान इस योजना की मिश्रित खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं.

पठान के बाद गदर 2 ने की बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड करीब 500 करोड़ का किया बिजनेस

22 साल बाद पर्दे पर लौटी तारा और सकीना की लव स्टोरी ने गदर मचा दी है. फिल्म इस साल की दूसरी ऐसी फिल्म में अपना नाम शुमार कर की है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड करीब 500 करोड़ के बिजनेस कर चुकी है. अमीषा पटेल और सनी देवल की जोड़ी ने कृति और प्रभास, सारा और विक्की कौशल जैसे यंग स्टार्स की जोड़ी को पछाड़ दिया. इन जोड़ी की आदुपुरुष और जरा हट के जरा बच के जैसी फिल्म वर्ल्डवाइड में यह आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं.

आपको बता दें, इस साल की फिल्म श्पठानश ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया था. यह फिल्म बेहद चर्चा में रही. अब इसके बाद अमीषा पटेल और सनी की फिल्म गदर 2 बॉलीवुड में दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है. सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर ये फिल्म वर्ल्डवाइड 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. इसके अलावा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक्शन ड्रामा इस फिल्म ने 375 करोड़ के आसपास कमाई की है.

गानों ने बनाया माहौल

फिल्म में कहानी के साथ गाने ने भी जोरदार माहोल बनाया है. मैं निकला गड्डी ले के..... जैसी गाने आज हर किसी की जुबान में हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए भी इस जोड़े ने बेहद मेहनत की है. दोनों ने कई शहरों में तारा और सकीना के लुक में ही प्रमोशन किया था.

युवाओं के अपने सपने होते हैं. इसे पूरा करने के लिए इनमें जुनून भी होता है. लेकिन कभी-कभी आर्थिक बाधा इन युवाओं के सपनों के आड़े आ जाती है. अपने सपने पूरे करने और सफल उद्यमी या व्यवसायी बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए आर्थिक समस्या बाधा न बने इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 553 युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हुए 215.59 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है. इसके तहत राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के रूप में गारंटी, प्रशिक्षण, अनुसरण और वित्तीय सहायता दी जा रही है. ताकि युवा अपनी कार्यक्षमता और योग्यता के अनुसार खुद का उद्योग और व्यवसाय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अपना योगदान दे सकें. इस योजना के माध्यम से युवा शक्ति का स्व-उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और कृषि संबंधी सहायक उद्योग धंधों का विकास करना भी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है. आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो. आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है.

अब युवाओं के सपनों और जुनून के आड़े नहीं आ रही आर्थिक बाधा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से खुद का व्यवसाय स्थापित कर बन रहे उद्यमी

भूपेश सरकार में हो रहा संस्कृति का संरक्षण, आदिवासी परब और परंपराओं को मिल रहा बढ़ावा

> आदिवासी संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है. इन्हें इनकी बोली, भाषा, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से जाना जाता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त 2022 से शासकीय अवकाश का लाभ देकर उनकी बरसों की मांग पूरी कर दी है. ताकि हमारे वनवासी अपने रीति रिवाजों और त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें.

छत्तीसगढ़ शासन आदिवासियों के विकास के लिए अनेकों काम कर रही है. आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक का परिक्षण और विकास योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा और श्रद्धा स्थलों पर देवगुड़ी के निर्माण और मरम्मत योजना संचालित है. विगत साढ़े चार सालों में देवगुड़ी ठाकुरदेव और सांस्कृतिक केंद्र घोटुल निर्माण, मरम्मत योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है.

प्रति देवगुड़ी की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति देवगुड़ी कर दिया गया. योजना के स्वरूप राशि में 5 गुना वृद्धि हुई है. इसके साथ ही अबुझमाड़िया जनजाति समुदायों में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ शासन ने विगत चार वर्षों में 2763 देवगुड़ी के लिए राशि 5185.83 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. साथ ही अबुझमाड़िया संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 104 घोटुल निर्माण के लिए राशि 470.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. आदिवासी के त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना अंतर्गत आदिवासियों में तीज, सरना, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली त्यौहारों, उत्सवों मेला, मड़ई, जात्रा आदि पर्व की परम्परागत संस्कृति का विकास और उनके आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है. अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत हर ग्राम पंचायत को राशि 10 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2023-24 में वित्तीय नियमानुसार प्रथम किस्त की राशि 5 हजार के मान से 5633 ग्राम पंचायतों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि 281.85 लाख हस्तांतरित की गई.

प्रदेश में चहुं ओर फैल रही शिक्षा की ज्योति, आत्मानंद स्कूल से संवरी विद्यार्थियों की जिंदगी, 3 लाख 90 हजार बच्चों को मिल रही उत्कृष्ट शिक्षा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना अब साकार हो रही है. प्रदेश की स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल से लाखों बेटे, बेटियों की जिंदगी संवर रही है. इसका लाभ सुदूर वनांचल हो या मैदानी जिले में आधुनिक शिक्षा की उजली तस्वीर देखने को मिल रही है. प्रदेश में वर्तमान सत्र 2023-24 में 377 अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय और 349 हिंदी माध्यम विद्यालय कुल 726 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं. स्कूल में 1 लाख 70 हजार बच्चे अंग्रेजी माध्यम और 2 लाख 20 हजार बच्चे हिन्दी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं.

राज्य सरकार की पहल से आज सुदूर अंचल के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खेलने के लिए बढ़िया मैदान, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जैसी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर अनेक पालकों के आर्थिक बोझ को कम कर दिया जिससे पालकों के मन की चिंता की लकीर दूर हो गई है. आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई करके बच्चे अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं. मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के बच्चों का आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ाया है.

अंग्रेजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थीयों ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में अपना स्थान बनाया है. इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, सुंदर भावन माडर्न पुस्तकालय, खेल मैदान, उत्कृष्ट प्रयोगशाला लैब आदि का बेहतर संचालन किया जा रहा है. जिससे प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के प्रति बच्चों और पालकों के मन में लोकप्रियता बढ़ी है. स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के संचालन से निर्धन गरीब वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त होने से पालकों में बहुत उत्साह है. जिसके कारण सभी जगह से और भी आत्मानंद स्कूल खोले जाने की मांग लगातार हो रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सरकारी शालाओं के बीच के अंतर को कम करने और बच्चों को बराबरी के अवसर देने के लिए यह योजना शुरू की है.

200 रुपये के बिल में 10 लाख जीतने का मौकाः सरकार निकालेगी लकी ड्रा

सरकार जनता के लिए एक योजना लेकर आई है. जल्द ही सभी को इसका लाभ मिलेगा. दरअसल, यह एक लकी ड्रा प्रक्रिया है. आपको बस संबंधित मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करना है और इसके लिए व्यक्तियों को इनाम मिलेगा. यह योजना क्या है? आपको बता दें कि सरकार जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना शुरू करने जा रही है.

दो अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि चालान प्रोत्साहन योजना के तहत, खुदरा विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं से प्राप्त चालान को मासिक या त्रैमासिक आधार पर ऐप पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है..

ऐप का नाम क्या है?

'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्राइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए चालान में विक्रेता का जीएसटीआईएन, चालान संख्या, भुगतान की गई राशि और कर राशि शामिल होनी चाहिए.

स्कीम क्या है

हर महीने 500 से अधिक कम्प्यूटरीकृत लकी ड्रा आयोजित किए जाएंगे जहां पुरस्कार राशि लाखों रुपये तक हो सकती है.

अधिकारियों ने कहा कि एक तिमाही में दो लकी ड्रा आयोजित किए जाएंगे, जहां पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है. बताया गया कि योजना अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और जल्द ही लॉन्च हो सकती है. वास्तव में, जीएसटी चोरी के खतरे को रोकने के लिए, सरकार ने पहले ही बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान अनिवार्य कर दिया है, जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है.

'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना बी2सी ग्राहकों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक चालान सृजन भी सुनिश्चित करेगी ताकि खरीदार लकी ड्रा में भाग लेने के लिए पात्र हो. इस योजना की संकल्पना इस तरह से की गई है कि नागरिकों और उपभोक्ताओं को माल और सेवा कर के अधीन वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक चालान की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

प्रयोजन क्या है

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है जो नागरिकों को खुद को पंजीकृत करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल पर चालान अपलोड करने में सक्षम करेगा. इस योजना से उपभोक्ताओं द्वारा अनुपालन व्यवहार को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने, कर अनुपालन व्यवसायों को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने और कर चोरी की जांच करने के कई उद्देश्यों की पूर्ति होने की उम्मीद है.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से समृद्ध होती खेती-किसानी

> धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला है. इससे किसानों स्थिति में बदलाव आया है और वह समृद्ध हुए हैं.

इस योजना के तहत किसानों को अब तक 20 हजार 103 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी गई है. जिसके चलते फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है. खेती - किसानी छोड़ चुके किसानों का रूझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है. 20 अगस्त 2023 को किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा. इसको मिलाकर इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली सीधी मदद की राशि 21,913 करोड़ रूपए हो जाएगी. किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपये की कर्जमाफी और 350 करोड़ रूपए के सिंचाई कर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों का उत्साह बढ़ा है और कृषि को संबल मिला है.

प्रदेश सरकार की नीतियों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों का ही यह परिणाम है कि राज्य में खेती- किसानी और किसानों के जीवन में खुशहाली आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर अधिक हो गया है. इसी अवधि में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख से बढ़कर 26 लाख के पार जा पहुची है. इन लगभग 5 सालों में किसान इसका अंदाजा सिर्फ राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की साल दर साल बढ़ती मात्रा से आसानी से लगाया जा सकता है. राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 80.30 लाख टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख टन, वर्ष 2020-21 में 92.06 लाख टन, वर्ष 2021-22 में 98 लाख टन तथा वर्ष 2022-23 में 107 लाख टन के रिकार्ड खरीदी समर्थन मूल्य हुई है.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में समृद्ध होती खेती-किसानी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसल को शामिल कर लिया है. कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादक किसानों को भी इस योजना के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए सब्सिडी दी जा रही है. राज्य में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन शुरू किया गया है. इसके उत्पादक किसानों को वाजिब मूल्य मिले इसलिए राज्य में बीते दो सालों से कोदो, कुटकी-रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है. वर्ष 2021-22 में 54 हजार क्विंटल कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर किसानों को इसके एवज में 16 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. वर्ष 2022-23 में 40 हजार क्विंटल खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 12 करोड़ रूपए है.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों की खेती या वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी 3 वर्षों तक दी जाएगी. छत्तीसगढ़ जैसे विपुल धान उत्पादक राज्य में फसल विविधीकरण समय की मांग और जरूरत है. सरकार इस बात को भलीभांति जानती है. राज्य में अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य की आबादी को पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न फसलों, दलहन-तिलहन का उत्पादन जरूरी है. इसकी पूर्ति फसल विविधीकरण को अपनाकर ही पूरी की जा सकती है. राज्य सरकार ने किसानों और वनवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि एवं वनोपज के वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को और अधिक लाभ मिल सके.

छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना ने भी राज्य में खेती-किसानी को काफी हद तक मजबूती दी है. नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 28 हजार नाले चिन्हित किए गए हैं. फिलहाल 14 हजार से अधिक नालों का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जिसके चलते नालों में जल ठहराव होने लगा है. फलस्वरूप भू-जल संवर्धन की स्थिति बेहतर हो रही है, नाले के किनारे वाले खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ी है दोहरी और नगदी फसलों का रकबा भी बढ़ा है. गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे 37 लाख क्विंटल कम्पोस्ट के उत्पादन और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है. किसानों के आमदनी में वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण जरूरी है. इससे खेती को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है. छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खेती-किसानी समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रही है.

मिनीमाता ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय क्षितिज पर दी नई पहचान

छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी. अपने प्रखर नेतृत्व क्षमता की बदौलत राष्ट्रीय नेताओं के बीच उनकी अलग पहचान थी. दलित शोषित समाज ही नहीं सभी वर्गो ने उनके नेतृत्व को मान्य किया था. उन्होंने संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मिनीमाता समाज हितैषी कार्यों की वजह से लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंची.

मिनीमाता ने समाजसुधार सहित सभी वर्गों की उन्नति और बेहतरी के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन्होंने जन सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानकर कार्य किया. उन्होंने नारी उत्थान, किसान, मजदूर, छूआ-छूत निवारण कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, निःशक्त व अनाथों के लिए आश्रम, महिला शिक्षा और जनहित के अनेक फैसलों और समाज हितैषी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया. मिनीमाता की राजनीतिक सक्रियता और समर्पण से पीड़ितों के अधिकार हेतु संसद में अनेक कानून बने.

मिनीमाता का मूल नाम मीनाक्षी देवी था. उनका जन्म 13 मार्च 1913 को असम राज्य के दौलगांव में हुआ. उन्हें असमिया, अंग्रेजी, बांगला, हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था. वह सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की साक्षात् प्रतिमूर्ति थीं. उनका विवाह गुरूबाबा घासीदास जी के चौथे वंशज गुरू अगमदास से हुआ. विवाह के बाद वे छत्तीसगढ़ आई, तब से उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. गुरू अगमदास जी की प्रेरणा से स्वाधीनता के आंदोलन, समाजसुधार और मानव उत्थान कार्यों में उन्होंने बढ़-चढ़कर मानव उत्थान कार्यों में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. स्वतंत्रता पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में सम्पन्न हुआ. मिनीमाता सन् 1951 से 1971 तक सांसद के रूप में लोकसभा की सदस्य रहीं. छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में दलितों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा. अविभाजित मध्यप्रदेश में बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर आरक्षित सीट से लोकसभा की प्रथम महिला सांसद चुनी गईं.

इसके बाद परिसीमन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची.

मिनीमाता की स्मृति में छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिये आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' कर दिया है. मिनीमाता के योगदान को चिरस्थाई बनाने के लिए तत्कालीन मध्यप्रदेश में हसदेव बांगो बांध को मिनीमाता के नाम पर रखकर किसानों के हित में किए गए उनके कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई. आज बिलासपुर और जांजगीर जिले के हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है. मिनीमाता ने उद्योगों में हमेशा स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की वकालत की. वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनीमाता की स्मृति में समाज एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनीमाता सम्मान की स्थापना की गई.

50 हजार लगाएं और लाखों में कमाएं, जानिए किस बिजनेस से आप बन सकते हैं घर बैठे लखपति?

क्या आप किसी अच्छे बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके और रिटर्न भी अच्छा मिले? मुर्गीपालन व्यवसाय जैसे विकल्प उन विकल्पों में से एक हो सकते हैं जो न केवल आपको लाभ दिलाएंगे बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे.

मुर्गीपालन का यह व्यवसाय शुरू करना आपकी कल्पना से कहीं अधिक आसान है. लगभग 40,000-50,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ, आप घर पर अपना खुद का खेती स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. यानी आंगन में या खेत में.

सरकार भी मदद करेगी

इस व्यवसाय को शुरू करने का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मदद मिलेगी जो मुर्गी पालन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और बढ़ावा दे रही हैं. सरकार पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है जो इसे ग्रामीण समुदाय के लिए और भी आकर्षक बनाती है. मुर्गियां पालने से आपको अच्छा-खासा मुनाफा मिल सकता है जबकि मुख्य बात मुर्गे की सही नस्ल का चयन करना है. यदि आप बड़े मुनाफे का लक्ष्य रख रहे हैं, तो कड़कनाथ, ग्रामप्रिया, स्वर्णनाथ, केरी श्यामा, निर्भीक, श्रीनिधि, वनराजा, कारी उज्जवल और कारी जैसी मुर्गियों की नस्लों पर विचार करें.

सरकार कितनी मदद करेगी?

केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करती है, जो आपके खर्च का 50% तक कवर करती है. अधिक जानने के लिए, आप आधिकारिक राष्ट्रीय पशुधन पोर्टल पर जा सकते हैं. इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी भी प्रदान करता है. ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं जहां से आप अपना पोल्ट्री उद्यम शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं.

शुरुआत कैसे करे

शुरुआत में आप केवल 10 से 15 चिकन से शुरुआत कर सकते हैं जिसके लिए आप लगभग 50,000 रुपये के निवेश पर विचार कर सकते हैं...और जब आपका चिकन बेचने का समय आएगा तो आपका मुनाफा आपके शुरुआती निवेश से दोगुना हो सकता है. इसके अलावा, मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे अतिरिक्त लाभदायक हो सकते हैं. एक देशी मुर्गी आमतौर पर सालाना लगभग 160 से 180 अंडे दे सकती है. इस प्रकार आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपके पास अच्छी संख्या में मुर्गियां होंगी तो आप कितना कमा पाएंगे. यानी आप हर साल लाखों रुपये कमा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बढ़ा मान: मेहनत का मिला वाजिब दाम

छत्तीसगढ़ के वन और आदिवासी सदियों से राज्य की पहचान रहे हैं. प्रदेश के लगभग आधे भू-भाग पर जंगल हैं, जहां छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती-फलती है. आदिवासियों का पूरा जीवन वनों पर आधारित होने के बावजूद समय के साथ-साथ उनकी वनों के साथ दूरी बढ़ती गई. भारत के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी जल-जंगल-जमीन पर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी. पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना इन्हीं अधिकारों की वापसी का सपना था.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों तक उनके सभी अधिकार पहुंचाने का वायदा किया था. साथ ही उन्हें हर तरह के शोषण से मुक्ति दिलाने का भी वायदा किया था. इन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार ने लगातार ऐसे कदम उठाए, जिनसे वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता फिर से मजबूत हुआ है और इन क्षेत्रों में विकास की नई सुबह हुई है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा नीति के चलते वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आने लगा है. श्री भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनका क्रियान्वयन किया. सरकार बनते ही इसकी शुरूआत लोहंडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापसी से की. बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांवों में एक निजी इस्पात संयंत्र के लिए 1707 किसानों से अधिग्रहित 4200 एकड़ जमीन वापिस की गई. इससे वहां के निवासियों को कृषि व्यवसाय के लिए पट्टे दिए जा सकेंगे. नए उद्योगों की स्थापना हो सकेगी. आजादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ क्षेत्र के 2500 किसानों को मसाहती खसरा प्रदान किया गया. अब तक अबूझमाड़ के 18 गांवों के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2 गांवों का सर्वे प्रक्रियाधीन है.

वनांचल में तेजी से बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा करके, 67 तरह के लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर संग्रहण, वेल्यूएडिशन और उनके विक्रय की व्यवस्था की गई. इनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और वेल्यू एडिशन करके राज्य सरकार ने न सिर्फ आदिवासियों की आय में बढ़ोत्तरी की है, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी निर्माण किया है. वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 में राज्य में 12 लाख 71 हजार 565 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसका कुल मूल्य 345 करोड़ रूपए है. वनोपज संग्रहण के लिए संग्राहकों को सबसे अधिक पारिश्रमिक देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है. तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई. योजना के अंतर्गत 3827 हितग्राहियों को 57.52 करोड़ रूपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है.

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति से देश-दुनिया को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जैसे गौरवशाली आयोजनों की शुरूआत राज्य सरकार द्वारा की गई. देवगुड़ियां और घोटुलों का संरक्षण और संवर्धन कर राज्य सरकार ने आदिम जीवन मूल्यों को सहेजा और संवारा है. श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने देवगुड़ी, ठाकुरदेव एवं सांस्कृतिक केन्द्र घोटुल निर्माण व मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है. वर्ष 2017-18 में प्रति देवगुड़ी के लिए एक लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाती थी, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021-22 में वृद्धि कर प्रति देवगुड़ी, घोटुल निर्माण, मरम्मत के लिए 5 लाख रूपए तक की सीमा कर दी है. विगत साढ़े तीन वर्षों में 2763 देवगुड़ी के लिए 51 करोड़ 55 लाख 83 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है.

इसके साथ ही अबूझमाड़िया जनजाति समुदायों में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है. वर्ष 2022-23 में नारायणपुर जिले में 104 घोटुल के निर्माण के लिए 4.70 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है. सरकार द्वारा आदिवासियों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने और इन त्यौहारों, उत्सवों को मूल रूप से आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखीकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू की गई है.

राज्य में वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जल-जंगल-जमीन पर आदिवासी समाज को संबल मिला है. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार के साथ-साथ रिजर्व क्षेत्र में वन अधिकार वनवासियों को दिए गए. विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज का महापर्व है. इसे पूरी गरिमा और भव्यता से मनाने की शुरूआत राज्य सरकार द्वारा की गई है. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का मान बढ़ाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

राज्य के वन क्षेत्रों में काबिज भूमि का आदिवासियों और पारंपरागत निवासियों को अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है. राज्य में निरस्त दावों की पुनः समीक्षा करके वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए जा रहे हैं. विगत पौने पांच वर्षों में 59,791 व्यक्तिगत, 25,109 सामुदायिक वन अधिकारी पत्र वितरित किए गए हैं. देश में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय करने की कार्यवाही छत्तीसगढ़ में की गई.

प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही धमतरी जिले में प्रारंभ की गई. राज्य में अब तक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को 23,571 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 2360 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 184 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है. वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों में से 17,411 वन अधिकार पत्र एकल महिलाओं (विधवा, निर्धन, अविवाहित, तलाकशुदा) को वितरित किए गए हैं.

राज्य में अब तक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में 18 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 3694 सामुदायिक वन अधिकार संसाधन मान्य किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 17,29,237 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है.

राज्य में बीते साढ़े 4 सालों में 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के अंतर्गत हितग्राहियों को 3,70,275 हेक्टेयर भूमि दी गई है. सामुदायिक वन अधिकार मान्यता के अनुसार 45,847 पत्र वितरित किए गए है, जिसके तहत 19,83,308 हेक्टेयर भूमि प्रदाय की गई है. 3,731 ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी कर 15,32,316 हेक्टेयर भूमि का अधिकार सौंपा गया है.

राज्य में वन अधिकार एवं मान्यता पत्र के अंतर्गत आबंटित भूमि 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का जरिया बन गई है. सामुदायिक वन अधिकार एवं वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त भूमि का फलदार वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है. अबूझमाड़ इलाके में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत तेजी पट्टे बांटे जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है.

ओड़िशा के बाद बस्तर में कांकेर वैली नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की पहल की गई है, इससे वन वासियों को रोजगार के साथ-साथ आय के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे. वन भूमि पट्टा धारियों की उपज के समर्थन मूल्य पर क्रय करने के अलावा उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया जा रहा है. वन अधिकार मान्यता पत्र हितग्राहियों की कृषि भूमि के समतलीकरण तथा मेढ़-बंधान कार्य में भी शासन द्वारा मदद की जा रही है. साथ ही उन्हें खाद-बीज एवं कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. राज्य में 41 हजार से अधिक हितग्राहियों को 11 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगार, पेयजल आदि से संबंधित जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. पेसा कानून से मिलेगा अधिकार- छत्तीसगढ़ सरकार पेसा कानून के नियमों को लागू करने के विषय में गंभीरता से प्रयास कर रही है. पेसा कानून के नियम बन जाने से अब इसका क्रियान्वयन सरल हो जाएगा. इससे आदिवासी समाज के लोगों में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना आएगी. ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा. ग्राम सभा के 25 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे और इस 50 प्रतिशत में एक चौथाई महिला सदस्य होंगे.

ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी ही होगा. महिला और पुरूष अध्यक्षों को एक-एक साल के अंतराल में नेतृत्व का मौका मिलेगा. गांव के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का अधिकार भी इन्हें होगा.

छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आया है. आदिवासियों की आय में वृद्धि और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है.

किसानों को मिल रहे समर्थन मूल्य से खुले समृद्धि के द्वार, मिलेट्स मिशन के तहत कोदो-कुटकी की खेती अन्नदाताओं के लिए साबित हुआ फायदे का सौदा

"छत्तीसगढ़ प्राकतिक संपदाओं के साथ-साथ अब कृषि की असीम संभावनों वाला राज्य बन गया है. प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत वादियों का नजारा जहां हरियाली, ठंडकदार मिट्टी की सौंध महक चारों ओर फैली रहती है. पहले यहां के कृषक केवल धान की खेती ही करते थे. लेकिन अब यहां धान के अलावा किसान अन्य फसल भी ले रहे हैं. जिससे प्रदेश में अब कृषि के लिए अनेक संभावनाएं बनी है."

ऐसे ही एक आत्मनिर्भर युवा किसान हैं मैनपाट के अभिषेक यादव. जो कि मिलेट्स समेत सब्जी और धान की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं. अभिषेक 17 वर्ष की उम्र से ही पढ़ाई के साथ-साथ खेती किसानी कर रहे हैं. अभिषेक बड़े पैमाने पर धान, मक्का, आलू, कोदो, कुटकी सहित स्थानीय फसल टाऊ की खेती कर रहे हैं.

आने-जाने के खर्च में हो रही बचत - किसान

कृषक अभिषेक कहते हैं कि आज किसान कोदो-कुटकी की खेती से भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि अब सरकार समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी कर रही है. वे कहते हैं कि पहले फसल बेचने में दिक्कत होती थी, अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट मिशन योजना के तहत कोदो कुटकी (मिझरी) फसल को यही बेच रहे हैं. आने-जाने के खर्च में बचत हो रही है और रेट भी अच्छा मिल रहा है. उन्होंने किसान युवा साथियों को कहा है कि खेती बाड़ी को भी रोजगार की तरह देखना चाहिए.

मिलेट्स की खेती को लेकर बढ़ा अन्नदाताओं का रुझान

छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के चलते राज्य में कोदो, कुटकी और रागी (मिलेट्स) की खेती को लेकर किसानों का रूझान बहुत तेजी से बढ़ा है. पहले औने-पौने दाम में बिकने वाला मिलेट्स अब छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे दामों में बिकने लगा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते राज्य में मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से किसानों को करोड़ों रुपये की आय होने लगी है. छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है. कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से और रागी की खरीदी 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है.

TATA की 4 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी इसी साल होगी लॉन्च

Tata Motors भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर काफी पॉपुलर है. वर्तमान में ये कंपनी ईवी दौड़ में शीर्ष पर है. अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाने के लिए, भारतीय कार निर्माता घरेलू बाजार में कई तरह की नई ईवी एसयूवी लॉन्च करने के लिए तैयार है. आइए, उनकी लॉन्च टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं.

पंच ईवी जल्द आएगी

टाटा मोटर्स आने वाले समय में अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच के इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है. दरअसल, टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में किफायती इलेक्ट्रिक कारों की लाइनअप बढ़ाने की कोशिश में है, ऐसे में माना जा रहा है कि पंच इलेक्ट्रिक को 10 लाख रुपये तक की शुरुआती एक्स शोरूम के साथ पेश कर सकती है और यह ईवी रेंज के मामले में भी अच्छी होगी.

हैरियर ईवी

2023 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित, हैरियर का इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव पूरी तरह से नई डिजाइन लैंग्वेज को स्पोर्ट करेगा, जो इसके आईसीई समकक्ष से काफी अलग है. हालांकि, आगामी हैरियर फेसलिफ्ट में ऑटो शो में सामने आए कॉन्सेप्ट से कुछ समानताएं होंगी. हैरियर ईवी ओमेगा-आर्क प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन को समायोजित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा. अगले साल यानी 2024 में किसी समय इसके बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप मिलेगा.

कर्व ईवी

टाटा मोटर की नई जेनरेशन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित, Tata Curvv EV का पिछले साल अप्रैल में अनावरण किया गया था. जेन 2 प्लेटफॉर्म और नेक्साम्न ईवी पर आधारित जेन 1 प्लेटफॉर्म का एक संशोधित संस्करण है और यह कई बॉडी प्रकारों और पावरट्रेन को समायोजित करने के लिए लचीला है. ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर 400-500 किलोमीटर की दावा की गई रेंज के साथ आएगी. जहां तक लॉन्च टाइमलाइन का सवाल है, इस ईवी के अगले साल 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसके बाद इसका आईसीई-संचालित संस्करण लॉन्च किया जाएगा.

भावों का होना मनुष्य जीवन की एक पहचान हैं..

हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विभिन्न प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर विकसित हुई है जैसे प्यार, ईर्ष्या, लालच, दया इत्यादि. इन सभी भावनाओं को समाज के प्रति प्रदर्शित करने का तरीका सभी का अलग-अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। प्राणी जगत के प्रति दयालुता प्रदर्शित करना बेहद ही पुण्य वाला काम है जो आज के व्यस्त जीवन में बहुत ही कम नजर आता है।

आजकल लोग खुद में ही इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और दूसरों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। दया किसी जरूरतमंद अथवा दीन-हीन के प्रति विनम्रता एवं विचारशीलता का होना है. यह गुण किसी-किसी के पास ही होता है. ईश्वर ने इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसे गुण प्रदान किए हैं और उनका होना उनके आस-पास के लोगों के लिए एक वरदान के समान है।

ऐसे व्यक्ति एक सुखद स्वभाव वाले और दूसरों के हित के लिए चिंतित रहते हैं. वे दूसरों की मदद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. दूसरों के लिए दया दिखाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छोटे से योगदान के रूप में हम सामने वाले को भावनात्मक समर्थन भी दे सकते हैं। मनुष्यों के साथ-साथ हम अन्य जीवों के प्रति भी करुणा से भरे कर्मों के द्वारा दयालुता को प्रदर्शित कर सकते हैं.जैसे की घर की छत पर आने वाली किसी चिड़िया को हम दाना डालकर दयालुता दिखा सकते हैं।

करुणा और दया से भरे इस कृत्य में ना तो अधिक मेहनत लगती है, ना ही अधिक रुपये. अत: हमें मनुष्यों के साथ-साथ जानवरों पर भी दया दिखानी चाहिए. हमें आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी भी कारण से राह चलते जानवरों को डंडा या पत्थर नहीं मारना चाहिए। यदि किसी जानवर को खाने या इलाज की जरूरत हो, तो उसकी व्यवस्था करके आप दया दिखा सकते हैं. बहुत सी बार घरों में अथवा किसी समारोह आदि में अतिरिक्त भोजन बच जाता है। इस भोजन को फेंकने की बजाए यदि जरूरतमंद और भूखों में बांट दिया जाए तो किसी भूखे का पेट भी भर जाएगा और पुण्य की भी प्राप्ति होगी. ऐसे ही असंख्य कर्म हैं जिनमें आप करुणा लाकर इस सृष्टि के प्रति दयालुता दिखा सकते हैं।

इन सभी कर्मों के द्वारा हम मनुष्य “कर्म में करुणा ही दयालुता है” पंक्ति को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं. यदि हम धर्मार्थ कार्य करते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव कराते हैं, तो हमें इतनी अधिक प्रसन्नता की अनुभूति होगी जितनी शायद अपने लिए लाखों रुपये खर्च करके भी ना हो

''कर्म में रखें हमेशा करुणा का भाव,
दयालुता दिखाने से कभी भी होता ना अभाव''

मनुष्यता इस पूरे संसार में जीवित रहने और दूसरों पर विश्वास करने का एक मूल मंत्र है। जीवन जीने की शैली बहुत ही सुगम तब हो जाती है जब विश्वास और दया का यह मंत्र लोगों के हृदय में निवास करता है। मानवता सिर्फ लोगों की मदद करना ही नहीं होता बल्कि मानवता जीवों पर दया दिखाना भी होता है. पृथ्वी पर जीवित सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम प्रजाति मानव को ही माना जाता है। मनुष्य में विद्यमान सर्वश्रेष्ठ गुण दयालुता है। दयालुता एक ऐसी आंतरिक विशेषता है जो हर किसी के पास नहीं होती. दुनिया की सबसे कीमती वस्तु भी दयालुता के आगे फीकी पड़ जाती है। इसीलिए दयालुता का गुण व्यक्ति के चरित्र और करुणा को प्रदर्शित करता है क्योंकि कहा भी जाता है कि - दया ही कर्म है और कर्म ही पूजा है

ORGALIFE®

Eat Organic, Stay Healthy

CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS

Range of 100% Natural & Eco Friendly Products

~~140/-~~ 120/- हिमालयन पिंक सॉल्ट	~~130/-~~ 115/- आर्गेनिक गुड	~~130/-~~ 115/- आर्गेनिक गुड पाउडर	~~150/-~~ 135/- गुड चना	~~115/-~~ 94/- गुड खुरचन	~~140/-~~ 125/- गुड पान
~~140/-~~ 120/- गुड पाचक	~~175/-~~ 160/- टी मसाला	~~180/-~~ 160/- रेड राइस	~~180/-~~ 165/- ब्लैक राइस	~~125/-~~ 155/- ब्राउन राइस	~~210/-~~ 190/- रामजीरा राइस
~~160/-~~ 145/- दुबराज राइस	~~170/-~~ 155/- हर्बल सोप	~~560/-~~ 545/- नारियल तेल	~~110/-~~ 95/- लाल मिर्च पाउडर	~~720/-~~ 700/- गिर गाय A2 घी	~~175/-~~ 154/- आम का अचार
~~130/-~~ 115/- मिक्स दाल	~~125/-~~ 110/- मसूर दाल	~~110/-~~ 90/- चना दाल	~~130/-~~ 115/- मूंग दाल (बिना छिलका)	~~130/-~~ 115/- उड़द दाल (छिलका)	~~125/-~~ 110/- झुरगा
~~160/-~~ 145/- काबूली चना	~~145/-~~ 120/- राजमा जम्मू	~~110/-~~ 85/- मल्टी ग्रेन दलिया	~~140/-~~ 120/- मूंग दाल (छिलका)	~~80/-~~ 60/- सुजी	~~95/-~~ 75/- साबुत चना
~~110/-~~ 85/- गेंहू आटा	~~115/-~~ 90/- चना बेसन	~~140/-~~ 120/- उड़द दाल(बिना छिलका)	~~145/-~~ 130/- अरहर दाल	~~110/-~~ 85/- रागी फ्लोर	~~90/-~~ 77/- राइस पोहा

More Then 100+ Organic Grocery Products

Scan & Shop Now

Add.: Magneto Mall, Basement infront of Smart Bazar, Raipur (C.G.)
E-kart Shop at Spree Walks, Marine Drive, Telibandha, Raipur (C.G.)

5 वर्ष जन स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के

साल 2018		अब
900	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर	5,372
5,186	उप-स्वास्थ्य केंद्र	5,208
785	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	796
6	शासकीय मेडिकल कॉलेज	11
36	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	52
0	हमर अस्पताल	4
76.40%	शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण का कवरेज	79.70%
221 प्रति लाख	मातृ मृत्यु दर	137 प्रति लाख
36.91%	कुपोषण दर	31.30%
2.63	मलेरिया एपीआई दर	0.92
204	शासकीय अस्पतालों में वेंटिलेटर	1,397
8,637 NHM	नई भर्तियां	13,467 NHM
6,835 (NHM) (2004-2018)	स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन	7,752 (NHM) (2019-2023)
61,39,487	शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज के लिए पात्र परिवार	72,65,000
30 हजार रु (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए सालाना नि:शुल्क इलाज की सीमा	5 लाख रु तक (डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना)
30 हजार रु (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना)	एपीएल श्रेणी के परिवारों के लिए सालाना नि:शुल्क इलाज की सीमा	50 हजार रु तक (डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना)
0	गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता	25 लाख रु तक (मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना)
0	कैंसर पीड़ितों के लिए नि:शुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा (दीर्घायु वार्ड) वाले जिला अस्पताल	17
0	किडनी रोगों से पीड़ितों के लिए नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा	28 (22 जीवन धारा एवं 6 न्यास/जीवन दीप समिति मद से)

- दुर्गम क्षेत्रों और बस्तियों में 1.69 करोड़ लोगों की जांच और नि:शुल्क उपचार
- श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में 72% तक की छूट पर दवाइयां, 74 लाख लोगों को मिली राहत
- देश की सबसे अधिक आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रु तक की आर्थिक सहायता

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. 12651/116